चिकित्सीय
आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए
कृपया 112 पर डायल करें।

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 संख्या 208 श्री विजय पुरम, मंगलवार, 04 अगस्त 2026 web: dt.andamannicobar.gov.in 2.00 रूपए

कम जोखिम वाले विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया हुई सरल

श्री विजय पुरम, 3 अगस्त। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के विद्युत विभाग ने आम जनता को सूचित किया है कि जन–केंद्रित एक प्रमुख पहल के तहत, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को सरल बनाना तथा प्रक्रियागत विलंब को कम करना है, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने कम जोखिम वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सुधार लागू किया है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 के अनुपालन में तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल (प्रशासक) की स्वीकृति से, प्रशासन ने विनियम–33 के अंतर्गत विचलन की अनुमति प्रदान करते हुए 20 किलोवाट तक के संयोजित भार वाले कम जोखिम श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य प्रमाणित परीक्षण प्रतिवेदनों के स्थान पर स्वयं–सत्यापित परीक्षण प्रतिवेदन/स्व–प्रमाणीकरण को स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की है। इस संबंध में अधिसूचना अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।

इस पहल से प्रक्रियागत विलंब में उल्लेखनीय कमी आने, दस्तावेज़ी आवश्यकताओं के सरल होने तथा पात्र घरेलू, वाणिज्यिक एवं अन्य कम जोखिम वाले उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराने में सुविधा होने की अपेक्षा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए अनुपालन संबंधी भार को कम कर प्रशासन ने सार्वजनिक सेवा प्रदायगी में सुधार की दिशा में एक और प्रगतिशील कदम उठाया है।

इस सुधार से विशेष रूप से परिवारों, छोटे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों तथा अन्य कम जोखिम वाले विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ होगा, क्योंकि इससे बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी एवं सुगम बनेगी, जबकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सभी लागू विद्युत सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन जारी रहेगा। यह प्रगतिशील कदम प्रशासन द्वारा नीतिगत सुधारों के माध्यम से सुशासन को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवा प्रदायगी में सुधार लाने तथा पूरे द्वीपसमूह में अधिक व्यवसाय–अनुकूल वातावरण विकसित करने के सतत प्रयासों की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन उच्चतम विद्युत सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करते हुए तीव्र, पारदर्शी एवं परेशानी–मुक्त सार्वजनिक सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल नागरिक–अनुकूल सुशासन तथा द्वीपसमूह में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन के निरंतर प्रयासों को प्रतिबिंबित करती है।

परिचालन हेतु सहमति (सीटीओ) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए यूसीएएमएस पोर्टल

श्री विजय पुरम, 3 अगस्त। अण्डमान तथा निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति (एएनपीसीसी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी उद्योगों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं (एचसीएफ), पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं, स्थानीय निकायों, आधारभूत संरचना परियोजनाओं तथा अन्य सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि परिचालन हेतु सहमति (सीटीओ) के लिए आवेदन अब यूनिफाइड कन्सेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (यूसीएएमएस) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

अण्डमान तथा निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति (एएनपीसीसी) की 39वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में, जहाँ भी लागू हो, वहाँ स्थापना हेतु सहमति (सीटीई) की स्थिति की परवाह किए बिना परिचालन हेतु सहमति (सीटीओ) के आवेदनों पर विचार किया जाएगा तथा उनका निस्तारण किया जाएगा, बशर्ते कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा अन्य लागू पर्यावरणीय अधिनियमों, नियमों एवं दिशा–निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया हो।

तदनुसार, ऐसे सभी उद्योगों एवं हितधारकों, जो वैध परिचालन हेतु सहमति (सीटीओ) के बिना संचालित हो रहे हैं, को सलाह दी जाती है कि वे यथाशीघ्र यूसीएएमएस पोर्टल **https://ucams.cpcb.gov.in** के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी आवश्यक सूचनाएँ एवं सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा तकनीकी सहायता के लिए आवेदक कार्यालय समय के दौरान अण्डमान तथा निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति (एएनपीसीसी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

'सागरिका' के विभागीय विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन सहायता हेतु आवेदन मांगे गए

श्री विजय पुरम, 3 अगस्त। स्थानीय स्तर पर पंजीकृत सभी स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, शिल्पकारों तथा हस्तशिल्प उत्पादों के निर्माण में संलग्न व्यक्तिगत व्यक्तियों, जो अण्डमान तथा निकोबार एम्पोरियम–"सागरिका" के विभागीय विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हैं, से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन, हस्तशिल्प उत्पादों के प्रस्तावित मूल्य, प्रत्येक नमूने के साथ तथा प्रत्येक नमूने के जेपीईजी प्रारूप में छायाचित्र संलग्न कर, स्वीकृति एवं अंतिम विक्रय मूल्य निर्धारण के लिए 19 अगस्त, 2026 तक अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत करें।

आवेदन प्रपत्र अण्डमान तथा निकोबार एम्पोरियम–"सागरिका" के सभी विक्रय केन्द्रों तथा सहायक निदेशक (तकनीकी) के कार्यालय एवं उद्योग विभाग के श्री विजय पुरम, बकुलतला, डिगलीपुर तथा कार निकोबार स्थित विस्तार कार्यालयों में उपलब्ध है।

प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन निर्धारित दिशा–निर्देशों के आधार पर किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले नए, उभरते तथा प्रथम बार आवेदन करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 3 मई, 2019 की अधिसूचित दिशा–निर्देश **https://industries.andamannicobar.gov.in/admin/whatsnewfile/20 26080332Notification%20ANE-Sagarika.pdf** पर देखे जा सकते हैं। तथापि, एएनई–एस दिशा–निर्देशों के खंड 9.15 एवं खंड 9.16 का उल्लंघन करने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, जबकि खंड 9.14 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतरिम शिथिलता प्रदान की गई है।

पुलिस समुद्री बल द्वारा एनएसीपी ओखा दल के माध्यम से तटीय पुलिसिंग पर कैप्सूल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू

श्री विजय पुरम, 3 अगस्त। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की तटीय सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अण्डमान तथा निकोबार पुलिस के समुद्री बल ने आज नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान (एनएससीबीपीटीआई), प्रोथरापुर में तटीय पुलिसिंग पर दो–सप्ताहीय कैप्सूल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शुभारम्भ किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 अगस्त से 14 अगस्त, 2026 तक राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी (एनएसीपी), ओखा, गुजरात के प्रशिक्षकों के एक दल द्वारा संचालित किया जा रहा है।

इस प्रशिक्षण का आयोजन पुलिस महानिदेशकों एवं पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन–2025 की सिफारिशों के अनुपालन में किया जा रहा है, जिसमें गृह मंत्रालय ने विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से समुद्री पुलिस कर्मियों की व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि पर बल दिया था।

वर्ष 2024 में राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी (एनएसीपी), ओखा के विशेषज्ञ संकाय सदस्यों ने श्री विजय पुरम का दौरा किया था तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान (एनएससीबीपीटीआई) के माध्यम से अण्डमान तथा निकोबार पुलिस के 319 पुलिस कर्मियों को विशेष समुद्री पुलिसिंग प्रशिक्षण प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त, 61 पुलिस कर्मियों ने राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी (एनएसीपी), ओखा, गुजरात में 10–सप्ताहीय समुद्री पुलिस आधारभूत पाठ्यक्रम (एमपीएफसी) सफलतापूर्वक पूर्ण किया है तथा वर्तमान में वे अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की विभिन्न समुद्री पुलिस इकाइयों में सेवाएं दे रहे हैं। उस कार्यक्रम से

शेष पृष्ठ 4 पर

द्वीपसमूह में गोजातीय पशुओं के लिए बांझपन निवारण शिविरों का आयोजन प्रारम्भ

श्री विजय पुरम, 3 अगस्त। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 अगस्त, 2026 से पूरे द्वीपसमूह में गोजातीय पशुओं के लिए बांझपन निवारण शिविरों का आयोजन प्रारम्भ कर दिया गया है। इन शिविरों का उद्देश्य वैज्ञानिक उपायों के माध्यम से प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार करना, गर्भधारण की दर बढ़ाना तथा दुग्ध विकास को प्रोत्साहित करना है।

गत 1 अगस्त को रवीन्द्र नगर पंचायत में बांझपन निवारण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कुल 35 पशुओं का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान 10 पशु गर्भित पाए गए, 20 पशुओं (जिनमें दुग्ध देने वाले पशु तथा 2 से 3 वर्ष आयु की कुछ बछियाएँ शामिल थीं) को कृमिनाशक दवा दी गई, ऋतु अवस्था में पाए गए एक पशु का कृत्रिम गर्भाधान किया गया तथा चार पशु प्रसव के 30वें दिन की अवस्था में पाए गए। पशुओं को हेपासिन पाउडर, मिनरल मिश्रण, रैफोक्सानाइड, ऑक्सीक्लोजानाइड. लेवामिसोल, एल्बेंडाजोल, टोनोफॉस्फान इंजेक्शन तथा मल्टीविटामिन इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए। इसके अतिरिक्त 30 किलोग्राम ज्वार (एमपी चारी) चारा बीज छह किसानों को प्रति किसान 5 किलोग्राम की दर से एक–एक बीघा क्षेत्र के लिए वितरित किए गए।

एक अन्य बांझपन निवारण शिविर ग्राम पंचायत सीपीघाट के अंतर्गत न्यू बिम्बलीटान गाँव में पशु चिकित्सालय गाराचरामा के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उनकी टीम द्वारा डॉ. पेरुमल, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीआईएआरआई के साथ आयोजित किया गया। शिविर में कुल 17 पशुओं का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान तीन बार–बार गर्भधारण में असफल रहने वाले पशु, अविकसित जननांगों के साथ मूक ऋतु का एक मामला तथा मूक ऋतु का एक अन्य मामला पाया गया। बार–बार गर्भधारण में असफल रहने वाले पशुओं का उपचार आइवरमेक्टिन, टोनोफॉस्फान तथा साइक्लोमिन से किया

गया। कृत्रिम गर्भाधान की सफलता बढ़ाने के उद्देश्य से छह आवारा सांडों का बधियाकरण किया गया। 27 गायों एवं 28 बकरियों को कृमिनाशक दवा दी गई, जबकि चार गायों को किलनीरोधी दवा दी गई। पशुपालकों को लिंग–चयनित वीर्य (एसएसएस) के लाभों के बारे में भी जानकारी दी गई।

एक अन्य बांझपन निवारण शिविर लाल पहाड़, पोर्ट मोट में भी आयोजित किया गया, जहाँ 10 पशुओं का परीक्षण किया गया। परीक्षण में दो पशु गर्भित, दो पशु ऋतु अवस्था में, दो पशु अनैस्ट्रस अवस्था में तथा चार पशु पूर्णतः सामान्य पाए गए। ऋतु अवस्था वाले दो पशुओं तथा सामान्य ऋतु चक्र वाले चार पशुओं का चयन भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी (ईटीटी) के पाँचवें चरण के लिए किया गया। चयनित पशुओं को कृमिनाशक गोलियाँ तथा मिनरल मिश्रण उपलब्ध कराया गया।

यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये शिविर गोजातीय पशुओं में बांझपन की समस्याओं के समाधान, वैज्ञानिक प्रजनन पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा द्वीपसमूह में पशुधन उत्पादकता में सुधार लाने के लिए विभाग के सतत प्रयासों का हिस्सा हैं।

न्यू वंडूर तट पर 'बाल अधिकार एवं उत्तरदायित्व' पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम संचालित

श्री विजय पुरम, 3 अगस्त। राज्य बाल संरक्षण समिति (एससीपीएस) द्वारा न्यू वंडूर तट में 'बाल अधिकार एवं उत्तरदायित्व' विषय पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का समन्वयन राज्य बाल संरक्षण समिति के कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा मादक पदार्थ मांग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीडीडीआर) तथा विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र (यूडीआईडी) योजना के सहयोग से किया गया। सभा को संबोधित करते हुए राज्य बाल संरक्षण समिति के कार्यक्रम प्रबंधक ने मिशन वात्सल्य के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए समुदाय की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास तथा समग्र विकास सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया।

प्रतिभागियों को किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की भूमिका के बारे में भी जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि बाल कल्याण समिति देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। 'पंख' स्वयंसेवी संस्था की संस्थापक श्रीमती कोमल आनंद ने बाल श्रम की रोकथाम पर एक संक्षिप्त सत्र प्रस्तुत किया तथा प्रत्येक बच्चे के शिक्षा, सुरक्षा एवं समग्र

विकास के अधिकार की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के प्रधान एवं पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, नौका संघ के अध्यक्ष सहित संघ के सदस्य, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारक तथा स्थानीय समुदाय के अन्य गणमान्य सदस्य भी उपस्थित रहे। स्थानीय क्षेत्र की महिलाओं ने भी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा संवादात्मक सत्र के दौरान अपने विचार एवं बहुमूल्य सुझाव सक्रिय रूप से साझा किए।

आयुष प्रकोष्ठ द्वारा नियमित योग कक्षाओं का आयोजन

श्री विजय पुरम, 3 जुलाई।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अंतर्गत कार्यरत आयुष प्रकोष्ठ द्वारा आम जनता के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वीपसमूह के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों एवं सामुदायिक स्थलों पर नियमित योग कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। चल रहे योग सत्रों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं	स्थान	दिन/समय
1	उप–ज़िला अस्पताल, डिगलीपुर, उत्तर अण्डमान (योग हॉल)	सोमवार से शुक्रवार, सायं 4 बजे से सायं 5 बजे तक
2	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद अस्पताल, मायाबंदर, उत्तर व मध्य अण्डमान (योग हॉल)	सोमवार से शुक्रवार, सुबह 5.30 बजे से सुबह 6.30 बजे तक
3	बिशप जॉन रिचर्डसन अस्पताल (बीजेआर), परका, कार निकोबार (योग हॉल)	सोमवार से शनिवार, सायं 5 बजे से सायं 6 बजे तक
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैम्पबेल बे	सोमवार से शुक्रवार, सायं 3.30 बजे से सायं 4.30 बजे तक
5	सामुदायिक भवन, ओंगी टेकरी, लिटिल अण्डमान	सोमवार से शनिवार, सायं 5 बजे से सायं 6 बजे तक
6	स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र, स्वराज द्वीप	सोमवार से शुक्रवार, सुबह 5 बजे से सुबह 6 बजे तक एवं सायं 3 बजे से साय 4.30 बजे तक
7	आयुष अस्पताल, जंगलीघाट, श्री विजय पुरम (योग हॉल)	सोमवार से शनिवार, सुबह 5 बजे से सुबह 6 बजे तक एवं सायं 4 बजे से साय 5 बजे तक
8	मरीना पार्क, श्री विजय पुरम (राज्य स्थापना स्मारक)	प्रतिदिन, सुबह 5.30 बजे से सुबह 6.30 बजे तक (बुधवार को छोड़कर)

'डीब्राइट' के एफओओ व एफपी तथा डिगलीपुर के बहुशिल्प संस्थान के एमएसबीटीई के अंतर्गत डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीसीएपी पोर्टल 6 अगस्त तक रहेगा खुला

श्री विजय पुरम, 3 अगस्त।

शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए बीटीईडी, दिल्ली के अंतर्गत एफओओ एवं एफपी कार्यक्रमों तथा डीब्राइट एवं राजकीय पॉलिटेक्निक, डिगलीपुर के एमएसबीटीई के अंतर्गत डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु सामान्य महाविद्यालय प्रवेश पोर्टल (सीसीएपी) 4 अगस्त से 6 अगस्त, 2026 तक खुला रहेगा।

अस्थायी मेरिट सूची 7 अगस्त, 2026 को प्रदर्शित की जाएगी, जबकि अंतिम मेरिट सूची 10 अगस्त, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

पात्र अभ्यर्थी सामान्य महाविद्यालय प्रवेश पोर्टल (सीसीएपी) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

क्रम सं	कार्यक्रम का विवरण	तिथि
डीब्राइट, श्री विजय पुरम : डीब्राइट ग्रीन बिल्डिंग		
1	सामान्य महाविद्यालय प्रवेश पोर्टल (सीसीएपी) का शुभारम्भ	4 अगस्त, 2026 से 6 अगस्त, 2026 तक
2	सीसीएपी पोर्टल पर अस्थायी मेरिट सूची का प्रदर्शन	7 अगस्त, 2026, सायं 5 बजे
3	दावा एवं आपत्तियाँ	8 एवं 9 अगस्त, 2026
4	दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन	10 अगस्त, 2026, सायं 5 बजे
5	एफओओ एवं एफपी हेतु परामर्श (श्रेणी–1, 2, 3–ए, 3–बी, 3–एबी, 4 एवं 5, टीएफडब्ल्यू, ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांग)	11 अगस्त, 2026
6	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (प्रथम वर्ष)/डीएचएमसीटी हेतु परामर्श (श्रेणी–1, 2, 3–ए, 3–बी, 3–एबी, 4 एवं 5)	12 अगस्त, 2026
राजकीय पॉलिटेक्निक, डिगलीपुर		
1.	कॉमन कॉलेज अडमिशन पोर्टल का खुलना	4 अगस्त, 2026 से 6 अगस्त, 2026
2.	डिप्लोमा कार्यक्रम (प्रथम वर्ष)–सिविल एवं कम्प्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी–सभी श्रेणियों हेतु परामर्श (स्थान : राजकीय पॉलिटेक्निक, सीतानगर, डिगलीपुर)	12 अगस्त, 2026

यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी परामर्श तिथियों पर अभ्यर्थियों का पंजीकरण सुबह 9 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा तथा परामर्श प्रक्रिया सुबह 10 बजे से प्रारम्भ होगी। अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल प्रमाण–पत्रों के साथ उनकी एक–एक छायाप्रति भी साथ लानी होगी। सभी दावे एवं आपत्तियाँ केवल ई–मेल आईडी कइतंपजंकउपेपवद/हउंपसण्बवउ के माध्यम से ही भेजी जाएँ। महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ही आवेदन कर दिया है, उन्हें सामान्य महाविद्यालय प्रवेश पोर्टल (सीसीएपी) पर पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

मायाबंदर कॉलेज में विषयवार संसाधन व्यक्तियों की अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित

मायाबंदर, 3 अगस्त।

महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय (एमजीजीसी), मायाबंदर, उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला द्वारा विषयवार तैयार की गई संसाधन व्यक्तियों की अंतिम मेरिट सूची महाविद्यालय की वेबसाइट **https://mggcm.and.nic.in** तथा **www.andamannicobar.gov.in** पर अपलोड कर दी गई है।

यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में चयनित अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे कार्यभार ग्रहण करने के समय सत्यापन हेतु अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के साथ, यदि लागू हो, तो स्थानीय प्रमाण–पत्र भी साथ लेकर आएँ।

पुलिस समुद्री बल द्वारा एनएसीपी ओखा दल के ——————पृष्ठ 1 का शेष

प्राप्त ज्ञान एवं कौशल आज भी उनके व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन में लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं।

द्वीपों से बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को नियमित 10–सप्ताहीय समुद्री पुलिस आधारभूत पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी भेजने में परिचालन संबंधी दायित्वों एवं जनशक्ति की सीमाओं जैसी व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, अण्डमान तथा निकोबार पुलिस ने गृह मंत्रालय से द्वीपों में ही कैप्सूल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया था। गृह मंत्रालय के निर्देशों पर कार्यवाही करते हुए राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी ने प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु एक सहायक कमांडेंट, एक उप–निरीक्षक तथा तीन प्रधान आरक्षियों सहित कुल पाँच सदस्यीय प्रशिक्षक दल को प्रतिनियुक्त किया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सभी तटीय पुलिस थानों में तैनात 60 पुलिस कर्मियों के लिए आयोजित किया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य उनकी व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करना तथा उन्हें तटीय पुलिसिंग एवं समुद्री विधि प्रवर्तन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक कौशल से सुसज्जित करना है, जिससे संघ राज्य क्षेत्र की समग्र तटीय सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सके।

दो–सप्ताहीय कैप्सूल पाठ्यक्रम को प्रतिभागियों को तटीय पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं का व्यापक ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें समुद्री सुरक्षा, तटीय निगरानी, नौवहन, समुद्री संचालन कला, नौकाओं पर चढ़ाई की प्रक्रिया, खोज एवं बचाव अभियान, समुद्री संचार, समुद्री विधि प्रवर्तन तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय जैसे विषय शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को पुलिस समुद्री बल में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक विशेष कौशल से सुसज्जित करना है।

उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस महानिदेशक श्री रवीन्द्र सिंह यादव, आईपीएस, उपस्थित रहे। उनके साथ अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती गीता रानी वर्मा, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक (पीएमएफ) श्रीमती श्वेता के. सुगथन, आईपीएस, एनएससीबीपीटीआई के प्रधानाचार्य श्री उमा शंकर, उप पुलिस अधीक्षक (पीएमएफ) श्री अंकिश यादव तथा एनएससीबीपीटीआई के उप–प्रधानाचार्य श्री चंदन जीएस भी उपस्थित थे।

अपने उद्घाटन संबोधन में पुलिस महानिदेशक ने समुद्री पुलिस कर्मियों की परिचालन तैयारी को सुदृढ़ करने और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की तटीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निरंतर क्षमता निर्माण, विशेष प्रशिक्षण तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के महत्व पर बल दिया।

यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अण्डमान तथा निकोबार पुलिस विशेष प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से अपने कर्मियों की क्षमताओं को निरंतर सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में मजबूत तटीय सुरक्षा तथा प्रभावी समुद्री विधि प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, आम जनता एवं मछुआरा समुदाय से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी विश्वसनीय सूचना अथवा संकट संबंधी सूचना को तत्काल दूरभाष संख्या 0319239247 अथवा टोल फ्री संख्या 1093/112 पर साझा करें, ताकि आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

मादक पदार्थ रोधी अभियान में एक और गिरफ्तार

मायाबंदर, 3 अगस्त।

मादक पदार्थों के खतरे के विरुद्ध अपने सघन अभियान को निरंतर जारी रखते हुए, उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला पुलिस ने अपने चल रहे मादक पदार्थ रोधी अभियान में एक और सफलता प्राप्त की है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 64 ग्राम संदिग्ध गांजा बरामद किया गया तथा एक व्यक्ति को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया।

इस संबंध में प्राप्त विशिष्ट सूचना के आधार पर कि स्वराजग्राम निवासी एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध गांजा बेचने के लिए जा रहा है, उप निरीक्षक मोहम्मद रफीक, प्रभारी पुलिस थाना डिगलीपुर के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस दल ने बहादुर टेकरी जंक्शन पर संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसके दौरान उसके कब्ज़े से लगभग 64 ग्राम संदिग्ध गांजा बरामद किया गया। बरामद मादक पदार्थ को विधिवत ज़ब्त कर लिया गया तथा कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत मामला दर्ज़ किया गया। बरामद मादक पदार्थ के स्रोत का पता लगाने तथा अवैध मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

उत्तर व मध्य अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में समुदाय के सदस्यों से इस निरंतर अभियान में पुलिस को सहयोग करने का आग्रह किया है। किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना निकटतम पुलिस थाने अथवा 100 एवं 112 हेल्पलाइन पर दें। सभी मुखबिरों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा उपयोगी एवं कार्रवाई योग्य सूचना देने वालों को उपयुक्त पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

युवा शतरंज खिलाड़ियों ने प्राप्त की पहली फिडे मानक रेटिंग

श्री विजय पुरम, 3 अगस्त।

यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में अण्डमान निकोबार शतरंज संघ (एएनसीए) ने घोषणा की है कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के एनसीएस की आराध्या राय (रेटिंग–1415) तथा एमजीआईएस के एम. ऋत्विक (रेटिंग–1451) ने आधिकारिक रूप से अपनी पहली फिडे मानक रेटिंग प्राप्त कर ली है, जो उनकी शतरंज यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

दोनों खिलाड़ियों ने फिडे रेटिंग प्रतियोगिताओं में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से बहुत कम आयु में अंतरराष्ट्रीय फिडे रेटिंग अर्जित की है। अण्डमान निकोबार शतरंज संघ (एएनसीए) ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी है।

दक्षिण अण्डमान अंचल में अंतर विद्यालय प्राथमिक स्तरीय फुटबॉल लीग–सह–नॉकआउट प्रतियोगिता 5 अगस्त से

श्री विजय पुरम, 3 अगस्त।

दक्षिण अण्डमान के उप शिक्षा कार्यालय द्वारा दक्षिण अण्डमान अंचल के प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालक एवं बालिका वर्ग की अंतर विद्यालय प्राथमिक स्तरीय फुटबॉल लीग–सह–नॉकआउट प्रतियोगिता–2026 का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नन्हे विद्यार्थियों में खेल भावना, शारीरिक तंदुरुस्ती, टीम भावना तथा समग्र विकास को प्रोत्साहित करना है। दक्षिण अण्डमान क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालय इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जो ज़मीनी स्तर पर फुटबॉल प्रतिभाओं की पहचान करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करेगी।

यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के लिए खुली यह प्रतियोगिता 5 अगस्त से 13 अगस्त, 2026 तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भातूबस्ती तथा राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मैदान में आयोजित की जाएगी। यह पहल खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने की शिक्षा विभाग की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

पांडि. विवि. की रिक्त सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तक बढ़ी

श्री विजय पुरम, 3 अगस्त।

शैक्षणिक सत्र 2026–2027 के लिए पांडिचेरी विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों में रिक्त बची हुई सीटों पर स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली विशेष प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 अगस्त, 2026 कर दी गई है।

यहाँ प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त, 2026 को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। परीक्षा केन्द्र पांडिचेरी विश्वविद्यालय परिसर, ब्रुक्शाबाद, श्री विजय पुरम रहेगा। प्रवेश–पत्र 6 अगस्त, 2026 से विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे।

इग्नू में नवीन प्रवेश एवं पुनः–पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ी

श्री विजय पुरम, 3 अगस्त।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई, 2026 सत्र के लिए अपने सभी कार्यक्रमों में नवीन प्रवेश तथा पुनः–पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त, 2026 कर दी है।

इग्नू स्नातकोत्तर, स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र कार्यक्रमों में विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता है। इग्नू द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं तथा इनका उपयोग पदोन्नति एवं संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षाओं के लिए भी किया जा सकता है। जो विद्यार्थी नियमित पद्धति से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं, वे भी द्वैध डिग्री योजना के अंतर्गत इग्नू में प्रवेश ले सकते हैं।

इग्नू में नवीन प्रवेश तथा पुनः–पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। विद्यार्थी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट **www.ignou.ac.in** पर जाकर ''स्टूडेंट सर्विसेज–एडमिशन'' अनुभाग के माध्यम से नवीन प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकते हैं तथा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध इग्नू समर्थ पोर्टल पर पुनः–पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

इग्नू शिक्षार्थियों के लिए कृषि, स्वास्थ्य विज्ञान, विदेशी भाषाएँ, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन, जनसंचार एवं पत्रकारिता, यात्रा एवं पर्यटन, अनुवाद अध्ययन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक श्रेणी के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है।

इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, श्री विजय पुरम के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि यदि किसी शिक्षार्थी को ऑनलाइन प्रवेश प्रपत्र अथवा पुनः–पंजीकरण प्रपत्र भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है, तो वे इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के सामने, वीआईपी रोड, जंगलीघाट डाकघर, श्री विजय पुरम या दूरभाष 03192–242888 अथवा 03192–230111, ई–मेल **rcportblair@ignou.ac.in** से संपर्क कर सकते हैं।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

आईटीआई में 170 पाठ्यक्रम, एआई–रोबोटिक्स समेत 32 आधुनिक ट्रेडों पर जोर

नई दिल्ली, 03 अगस्त।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) देशभर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्यढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप 170 पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

डीजीटी के अनुसार आईटीआई के माध्यम से संचालित सभी पाठ्यक्रम एनएसक्यूएफ के अनुरूप हैं और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) से अनुमोदित हैं। तकनीकी प्रगति, व्यावसायिक मानकों में बदलाव और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्याओं का पुनरीक्षण आवश्यकता के आधार पर अथवा एनसीवीईटी के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाता है। वर्तमान में सीटीएस के 40 पाठ्यचर्याओं का पुनरीक्षण पूरा किया जा चुका है।

पाठ्यचर्या समीक्षा और पुनरीक्षण को सतत एवं आवश्यकता आधारित प्रक्रिया के रूप में अपनाया गया है। इसमें उभरती प्रौद्योगिकियों, बदलते व्यावसायिक मानकों, उद्योग की मांग, रोजगार के रुझानों, शिक्षुता की जरूरतों, प्रशिक्षण परिणामों और कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त फीडबैक का आकलन किया जाता है। इसके आधार पर पाठ्यक्रमों में आवश्यक बदलाव किए जाते हैं।

पाठ्यक्रमों में उद्योग 4.0 के अनुप्रयोगों, कृत्रिम मेधा (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), स्वचालन, हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डिजिटल कौशल, उद्यमशीलता, कार्यस्थल सुरक्षा, पर्यावरणीय टिकाऊपन और परिणाम आधारित शिक्षण जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षुओं को बदलती तकनीकी और औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है।

पाठ्यचर्या पुनरीक्षण के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, उद्योग प्रतिनिधियों, क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी), राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई), विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, नियोजकों और कार्यान्वयन एजेंसियों समेत विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार अन्य मंत्रालयों और विभागों को भी प्रक्रिया में शामिल किया जाता है।

महिला अभ्यर्थी निर्धारित प्रवेश अर्हताओं के आधार पर सीटीएस के तहत सभी एनएसक्यूएफ–अनुरूप पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकती हैं। इनमें 32 नव युगीन और भावी कौशल पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। 170 पाठ्यक्रमों में ड्रेस मेकिंग, सिलाई प्रौद्योगिकी, सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स (कढ़ाई), कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी और स्पा थेरेपी सात ऐसे पाठ्यक्रम हैं, जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से संचालित किए जाते हैं।

भारत सरकार ने सभी राजकीय और निजी आईटीआई में सभी पाठ्यक्रमों के तहत महिला अभ्यर्थियों के लिए

30% सीटों का आरक्षण मंजूर किया है। इन सीटों को संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की सामान्य आरक्षण नीति के अनुसार भरा जा सकता है।

डीजीटी ने भविष्य की उद्योग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम मेधा, मेकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, औद्योगिक रोबोटिक्स, उन्नत विनिर्माण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिकी, सेमीकंडक्टर, हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 32 नव युगीन एवं आधुनिक कौशल पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। इसके अलावा उद्योग की बदलती मांग और भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरूप कौशलोन्नयन एवं पुनर्कौशलीकरण के लिए नए अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी विकसित किए जा रहे हैं।

सीटीएस के तहत आधुनिक कौशल पाठ्यक्रमों में 5जी नेटवर्क टेक्नीशियन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (3डी प्रिंटिंग) टेक्नीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, साइबर सिक्योरिटी असिस्टेंट, डेटा एनोटेशन असिस्टेंट, ड्रोन पायलट (जूनियर), ड्रोन टेक्नीशियन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नीशियन और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एवं डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं।

इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन (स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट हेल्थकेयर), मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर टेक्नीशियन, सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल), टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स, विंड प्लांट टेक्नीशियन, न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट और स्मार्टफोन टेक्नीशियन कम ऐप टेस्टर जैसे ट्रेड भी शामिल किए गए हैं।

नए पाठ्यक्रम शुरू करने और मौजूदा पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षण के लिए श्रम बाजार की मांग का आकलन कौशल अंतराल अध्ययनों तथा उद्योगों, सेक्टर कौशल परिषदों, जिला कौशल समितियों, नियोजकों, उद्योग संघों, राज्य सरकारों, प्रशिक्षण संस्थानों और विषय विशेषज्ञों के साथ लगातार परामर्श के जरिए किया जाता है। पाठ्यक्रम तैयार करते समय उद्योग की जरूरतों, तकनीकी प्रगति, व्यावसायिक मानकों, रोजगार के रुझानों, शिक्षुता के अवसरों और उभरती कौशल जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है।

सरकार की यह परामर्श आधारित व्यवस्था यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि आईटीआई पाठ्यक्रम उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बने रहें। इसके जरिए प्रशिक्षुओं की रोजगार–क्षमता बढ़ाने और उन्हें अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। (इनपुटः पीआईबी)

शपथ–पत्र

मैं, सेवा संख्या 5354273K, पद नायक (NK), नाम प्रणाम राय (PRANAM RAI), वर्तमान में 2/4 जी.आर. इन्फैंट्री बटालियन, गोरखा रेजिमेंट, ब्रिचगंज मिलिट्री स्टेशन, श्री विजय पुरम में निवासरत हूँ, सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेकर निम्नलिखित कथन करता हूँ:

(क) कि मेरी पत्नी का नाम मेरी सेवा अभिलेखों में रोजी प्रधान राय (ROZEE PRADHAN RAI) दर्ज है। जबकि मेरी पत्नी के आधार कार्ड के अनुसार उनका नाम रोजी प्रधान (ROZEE PRADHAN) है।

(ख) कि मैं अपनी सेवा अभिलेखों में अपनी पत्नी का नाम रोजी प्रधान (ROZEE PRADHAN) के रूप में दर्ज/संशोधित कराना चाहता हूँ।

(ग) कि मैं यह शपथ–पत्र मेरी पत्नी के वास्तविक नाम के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

(घ) कि उपर्युक्त कथन मेरी जानकारी, सूचना एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं तथा इनमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया या दबाया नहीं गया है।

सत्यापन

मैं, उपर्युक्त नामित शपथकर्ता, सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषणा एवं सत्यापन करता हूँ कि इस शपथ–पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं तथा इसमें कोई भी तथ्य छिपाया या दबाया नहीं गया है।

दिनांकः 30/07/2026

स्थानः श्री विजय पुरम

शपथकर्ता

ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति जताई

नई दिल्ली, 03 अगस्त।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188 हजार बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया।

सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान सहित सात ओपेक प्लस सदस्यों ने बैठक के बाद जारी बयान में, कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य, तेल बाजार की स्थिरता को बनाए रखना और भागीदार देशों को पिछले अतिरिक्त उत्पादन की भरपाई में तेजी लाने की अनुमति देना है।

राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के प्रदर्शन पर खेल मंत्री ने कहा–भारत ने बढ़ती खेल ताकत का किया प्रदर्शन

नई दिल्ली, 03 अगस्त (हि.स.)।

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि भारत ने सीमित खेलों वाले इस संस्करण में भी अपनी बढ़ती खेल ताकत का शानदार परिचय दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2030 में अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का शताब्दी संस्करण भारत इतिहास के सबसे यादगार आयोजनों में से एक बनाएगा।

श्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 का समापन शानदार चौथे स्थान के साथ किया। ग्लासगो 2026 का यह संस्करण सीमित खेलों वाला था और इसमें कई ऐसे खेल शामिल नहीं थे जिनमें भारत पारंपरिक रूप से मजबूत रहा है। इसके बावजूद भारतीय दल ने बर्मिंघम 2022 में समान खेलों में जीते गए 30 पदकों की तुलना में इस बार 39 पदक जीतकर उल्लेखनीय सुधार किया है।

श्री मांडविया ने आगे कहा, अब जब भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों के शताब्दी संस्करण की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, हमारा संकल्प है कि हम खेलों के इतिहास के सबसे शानदार आयोजनों में से एक का आयोजन करें।

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। भारतीय खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक अपने नाम किए। सीमित खेलों के बावजूद भारत ने मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, जूडो, पैरा खेलों और भारोत्तोलन जैसे खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की।

पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 70 स्वर्ण सहित कुल 171 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। इंग्लैंड 110 पदकों के साथ दूसरे और कनाडा 62 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। मेजबान स्कॉटलैंड ने भी 39 पदक जीते, लेकिन भारत से कम रजत पदक होने के कारण उसे पांचवें स्थान से संतोष करना पड़ा।

11 दिनों तक चले इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख खेल शक्तियों में शामिल है और अब उसकी नजरें अहमदाबाद 2030 में सफल मेजबानी के साथ–साथ और भी बेहतर प्रदर्शन पर टिकी हैं।

दिल्ली में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का भव्य समापन, भारत के खाते में 16 पदक

नई दिल्ली, 03 अगस्त (हि.स.)।

दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का रविवार को भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में विजेता खिलाड़ियों को पदक एवं सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि राष्ट्रीय राजधानी को केवल देश की राजनीतिक राजधानी ही नहीं, बल्कि भारत की स्पोर्ट्स कैपिटलश के रूप में भी स्थापित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 जुलाई से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 25 कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ियों की भागीदारी ने दिल्ली की विश्वस्तरीय खेल आयोजनों की मेजबानी क्षमता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने इसे खेल उत्कृष्टता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान–प्रदान का उत्सव बताया।

चौंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 16 पदक अपने नाम किए। भारत ने पुरुष

और महिला टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने के अलावा पुरुष एवं महिला एकल, महिला युगल, मिश्रित युगल तथा पुरुष युगल स्पर्धाओं में भी स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल कर प्रतियोगिता में अपना दबदबा कायम रखा। भारतीय खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन ने विश्व मंच पर भारतीय टेबल टेनिस की बढ़ती ताकत को एक बार फिर साबित किया।

संग्रहालयों और सांस्कृतिक संस्थानों का डिजिटल रूपांतरण

नई दिल्ली, 03 अगस्त।

संग्रहालय संग्रहों और अभिलेखीय संसाधनों के डिजिटलीकरण के लिए पुणे स्थित सी–डीएसी के विकसित जतन (जेएटीएएन) सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए, संस्कृति मंत्रालय डिजिटल अभिलेखन और संग्रह प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न पहल कर रहा है ताकि हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को डिजिटल रूप से संरक्षित किया जा सके। भारत के संग्रहालय पोर्टल के माध्यम से एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनाया गया है, जहां राष्ट्रीय स्तर के आठ संग्रहालयों, दो एएसआई साइट संग्रहालयों और पुणे स्थित डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर संग्रहालय के डिजिटल संग्रह उपलब्ध हैं। अब तक के डिजिटल लेखों को देखने के लिए निम्नलिखित लिंक https://museumsofindia.gov.in/repository पर जाएं।संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किए गए ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य देश की विशाल हस्तलिखित धरोहर की रक्षा करना और भावी पीढ़ियों के लिए इसकी सभ्यतागत ज्ञान परंपराओं को पुनर्जीवित करना है। अभी ज्ञान भारतम पोर्टल पर आम लोगों के लिए डिजिटल रूप में 3.5 लाख से ज़्यादा पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, जिन्हें इस लिंक पर जाकर देखा जा सकता है https://gyanbharatam.com/. आईजीएनसीए ने अपनी नियमित शैक्षणिक और अभिलेखीय गतिविधियों के माध्यम से मिथिला कला, परंपराओं और पांडुलिपियों के विभिन्न पहलुओं का दस्तावेजीकरण, अनुसंधान, प्रकाशन और डिजिटल संरक्षण किया है।

इतिहास के पन्नों में 04 अगस्तः एशिया के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर 'अप्सरा' की हुई शुरुआत

नई दिल्ली, 03 अगस्त (हि.स.)।

भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इतिहास में 04 अगस्त 1956 एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज है। इसी दिन भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर 'अप्सरा' शुरू हुआ था। इसके साथ ही भारत न केवल परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा, बल्कि एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित करने वाला देश भी बना।

भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ होमी जहांगीर भाभा ने जनवरी 1954 में एटॉमिक एनर्जी इस्टैब्लिशमेंट, ट्रॉम्बे (एईईटी) की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य देश में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान को नई दिशा देना था। इसके लिए देशभर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक मंच पर लाकर अनुसंधान रिएक्टर विकसित करने की योजना बनाई गई।

15 मार्च 1955 को भारत के पहले अनुसंधान रिएक्टर के निर्माण का औपचारिक निर्णय लिया गया। डॉ भाभा के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे 'स्विमिंग पूल प्रकार' के रिएक्टर की परिकल्पना की, जिसकी क्षमता 01 मेगावाट थर्मल निर्धारित की गई। रिएक्टर के निर्माण का कार्य ट्रॉम्बे स्थित वर्तमान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) परिसर में शुरू हुआ। यह महाराष्ट्र के मुंबई में है। निर्माण के दौरान सबसे बड़ी चुनौती परमाणु ईंधन की उपलब्धता थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटेन ने रिएक्टर के लिए आवश्यक संवर्धित यूरेनियम उपलब्ध कराया।

भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की अथक मेहनत से महज 15 महीनों में रिएक्टर का निर्माण पूरा हो गया। इसके बाद 04 अगस्त 1956 को 'अप्सरा' का सफलतापूर्वक संचालन शुरू हुआ। यह उपलब्धि भारत के वैज्ञानिक विकास और तकनीकी क्षमता का प्रतीक बनी।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1666 – नीदरलैंड और इंग्लैंड के बीच नौसैनिक युद्ध हुआ।
1870 – ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई।
1886 – कोलंबिया ने संविधान अंगीकार किया।

1914 – इंग्लैंड द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा।
1915 – जर्मन सेना ने वारसॉ पर कब्जा किया।
1930 – यूरोपीय देश बेल्जियम में आज ही के दिन बाल मजदूर कानून बनाया गया था।
1935 – गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट 1935 को ब्रिटिश राजशाही की मंजूरी मिली।
1947 – जापान में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी।
1954 – पाकिस्तान सरकार ने हाफिज जलंधरी द्वारा लिखे गीत को राष्ट्रगान के रूप में अपनाने पर सहमति दी।
1956 – भारत ने अपना पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा शुरू किया था।
1967 – भारत में दुनिया का सबसे लंबा नागार्जुन सागर बांध बना।
1967 – अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।
1997 – मो. खघतमी द्वारा ईरान के नये राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण।
1999 – चीन ने अमेरिकी सेना के विमानों की नियमित उड़ानों को हांगकांग में उतरने की अनुमति देने से इंकार किया।
2001 – रूस व उत्तरी कोरिया में सामरिक समझौता।
2004 – नासा ने एल्टिक्स सुपर कम्प्यूटर केसी को कल्पना चावना नाम दिया।
2007 – मंगल ग्रह की खोज के लिए फीनिक्स मार्स लैंडर नामक एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया।
2008 – सरकार ने भारतीय जहाजरानी निगम (एससीआई) को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया।

कार्ड पर अब नहीं छपेगा लंबा पता! सुरक्षा से लेकर फोटो शेयरिंग तक, शादियों में कैसे गेम चेंजर बना क्यूआर कोड

नई दिल्ली, 03 अगस्त।

तकनीक में विकास के साथ अब शादियों में काफी बदलाव आ रहा है। शादियां अब सिर्फ सजावट और रस्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसमें तकनीक भी शामिल हो गई है। अमेरिका की शादियों में अब QR कोड का काफी इस्तेमाल हो रहा है।

शादियों में क्यूआर कोड के बढ़ते इस्तेमाल के पीछे मेहमानों और दूल्हा–दुल्हन की सुविधा से जुड़े कारण हैं। दरअसल, शादियों में कई तरह के ताम–झाम होते हैं। वेन्यू क्या है, ड्रेस कोड क्या रहेगा, फोटोज कहां लेनी है और हमारी फोटोज हमें कैसे मिलेंगी, जैसी सभी उलझनों को दूर करने के लिए अब शादियों में क्यूआर कोड का चलन बढ़ गया है।

शादी के कार्ड्स और सेव–द–डेट नोट में क्यूआर कोड का खूब इस्तेमाल हो रहा है। एक वेडिंग प्लेटफॉर्म के मुताबिक, पिछले दो सालों में इंविटेशन कार्ड पर क्यूआर कोड के इस्तेमाल में लगभग 42.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं 2026 के एक सर्वे में पता चला है कि इस साल 59% कपल्स ने अपने शादी के कार्ड पर क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया। जबकि साल 2021 में ये आंकड़ा सिर्फ 7% तक था।

इंविटेशन कार्ड पर बने क्यूआर कोड को स्कैन करते ही मेहमानों को शादी से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां मिल जाती हैं। वेन्यू से लेकर ड्रेस कोड और फोटो अपलोड करने के लिंक तक, सबकुछ सिर्फ एक क्यूआर कोड को स्कैन करते ही पता चल जाता है। इससे इंविटेशन कार्ड पर बहुत सारी डीटेल्स नहीं लिखनी पड़ती और कागज की बचत होती है, जो दूल्हा–दुल्हन की जेब और पर्यावरण के

लिए काफी फायदेमंद होता है।

शादी मेहमानों के लिए भी काफी कन्फ्यूजिंग हो जाती है। किस दिन कौन–सा फंक्शन है और क्या ड्रेस कोड है, जैसे सवाल अब पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सभी जानकारियां शादी के कार्ड पर बने क्यूआर कोड को स्कैन करते ही मिल जाती है।

फंक्शन कितने बजे से शुरू होंगे, आपकी सीट नंबर क्या है, गाड़ी कहां पार्क करनी है, जैसी सभी जरूरी जानकारियां क्यूआर कोड से मिल जाती हैं। साथ ही, फोटोज अपलोड और शेयर करने का डायरेक्ट लिंक भी क्यूआर कोड से मिल जाता है।

क्यूआर कोड सुविधा के साथ–साथ सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाल ही में पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट की शादी में वेन्यू में एंट्री करते समय बिना क्यूआर कोड दिखाए अंदर नहीं जा सकते थे। ऐसा सुरक्षा के लिहाज से किया गया था, ताकि सिर्फ वहीं लोग अंदर आ सकें, जिन्हें आमंत्रित किया गया है। इतना ही नहीं, कई लोग अब क्यूआर कोड का इस्तेमाल किसी दूसरी भाषा में मिली बधाई को ट्रांसलेट करने के लिए भी कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक लोकसभा में पारित

नई दिल्ली, 03 अगस्त (हि.स.)। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और न्यायिक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने संबंधी विधेयक सोमवार को बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया। विधेयक में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान किया गया है।

लोकसभा ने आज सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करता है। हंगामें के बीच विधेयक को पारित कर दिया गया।

विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कहा कि संशोधन न्यायिक क्षेत्र में सुधारों की शृंखला का महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि संविधान पीठों के गठन के कारण नियमित मामलों की सुनवाई के लिए उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है। ऐसे में अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता महसूस की गई। इस संबंध में लाए गए अध्यादेश को विधिक स्वरूप देने के लिए विधेयक सदन के समक्ष रखा गया है।

उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुरूप समय–समय पर बदलती आवश्यकताओं के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती रही है। संविधान लागू होने के समय मुख्य न्यायाधीश सहित कुल आठ न्यायाधीशों का प्रावधान था। बाद में 1956 के कानून के माध्यम से यह संख्या बढ़ाई गई। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य बढ़ते लंबित मामलों का प्रभावी निस्तारण और न्यायिक कार्यप्रणाली को अधिक सक्षम बनाना है।

केंद्र ने वाहनों में वी–टू–वी संचार प्रणाली लागू करने का मसौदा जारी किया

नई दिल्ली, 03 अगस्त (हि.स.)। देश में सड़क सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने मोटर वाहनों में वाहन–से–वाहन (वी–टू–वी) संचार प्रणाली चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का मसौदा अधिसूचना जारी कर सुझाव एवं आपत्तियां मांगी हैं।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि प्रस्ताव के अनुसार एक अक्टूबर 2027 से निर्मित एल, एम और एन श्रेणी के उन वाहनों पर एआईएस–230 मानक लागू होगा, जिनमें वी–टू–वी संचार प्रणाली लगी होगी। वहीं, एक अक्टूबर 2028 से निर्मित सभी एल, एम और एन श्रेणी के वाहनों में एआईएस–230 मानक के अनुरूप वी–टू–वी संचार प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा।

मंत्रालय के अनुसार वी–टू–वी संचार प्रणाली के माध्यम से आसपास चल रहे वाहन वास्तविक समय में अपनी गति, स्थिति, दिशा और त्वरण जैसी जानकारियां एक–दूसरे से साझा कर सकेंगे। इससे अचानक ब्रेक लगने, आगे टक्कर की आशंका, असुरक्षित लेन परिवर्तन तथा आपातकालीन वाहनों के आने जैसी परिस्थितियों में समय रहते चालक या वाहन प्रणाली को चेतावनी मिल सकेगी।

पारंपरिक सुरक्षा प्रणालियां मुख्य रूप से वाहन में लगे सेंसर और चालक की प्रतिक्रिया पर निर्भर रहती हैं, जबकि वी–टू–वी प्रणाली चालक की सीधी दृष्टि से परे की जानकारी भी उपलब्ध करा सकेगी। इससे उन्नत चालक सहायता प्रणाली (एडीएएस), दुर्घटना रोकथाम, कनेक्टेड मोबिलिटी और भविष्य की बुद्धिमान परिवहन प्रणाली को मजबूती मिलेगी।

मंत्रालय ने बताया कि एआईएस–230 मानक में रेडियो प्रदर्शन, आवृत्ति स्थिरता, रिसीवर संवेदनशीलता, वैश्विक उपग्रह नौवहन प्रणाली (जीएनएसएस), विद्युत आपूर्ति, विद्युत–चुंबकीय अनुकूलता, साइबर सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा संबंधी प्रदर्शन मानकों को शामिल किया गया है। यह मानक 5.875 गीगाहर्ट्ज से 5.925 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में सेलुलर व्हीकल–टू–एवरीथिंग (सी–वी2एक्स) तकनीक पर आधारित ऑन–बोर्ड यूनिट के लिए तैयार किया गया है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत आपातकालीन ब्रेक चेतावनी, आगे टक्कर की चेतावनी, गलत दिशा में वाहन चलने की सूचना तथा आपातकालीन वाहन चेतावनी जैसी सुरक्षा सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

मंत्रालय ने बताया कि दूरसंचार विभाग ने 10 जून 2026 की अधिसूचना के माध्यम से 5.875 से 5.925 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड के उपयोग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है। वी–टू–वी प्रणाली के विकास और क्रियान्वयन के लिए गठित कार्यबल ने भी सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए 5.9 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड के उपयोग की सिफारिश की थी। मंत्रालय ने कहा कि मसौदा नियमों पर 30 दिन के भीतर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।

थाईलैंड के सिल्पकॉर्न विश्वविद्यालय में खुलेगा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का विदेशी अध्ययन केंद्र

नई दिल्ली/बैंकॉक, 03 अगस्त (हि.स.)। भारत और थाईलैंड के बीच सोमवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। यह समझौता दिल्ली स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और बैंकॉक स्थित सिल्पकॉर्न विश्वविद्यालय के बीच हुआ है।

इस अवसर पर थाईलैंड में भारत के राजदूत पुनीत अग्रवाल ने साक्षी के रूप में सहभागिता करते हुए दोनों विश्वविद्यालयों को बधाई दी और इसे भारत एवं थाईलैंड के बीच साझा रुचि के क्षेत्रों में शैक्षणिक सहयोग के विस्तार की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया।

समारोह में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी, सिल्पकॉर्न विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रो. डॉ. तनासैत डावहिरुनपत, पद्मश्री असिस्टेंट प्रो. डॉ. चिरापत प्रपंडविद्या, अमरजीव लोचन प्रो. मधुकेश्वर भट्ट सहित दोनों देशों के अनेक शिक्षाविद् एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

इस समझौते के अंतर्गत सिल्पकॉर्न विश्वविद्यालय में स्थापित संस्कृत अध्ययन केंद्र को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विदेशी अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस केंद्र की स्थापना पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज के कार्यकाल में हुई थी। अब यह पहल विदेशों में संस्कृत, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रसार को संस्थागत स्वरूप प्रदान करेगी।

बैठक में थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास द्वारा दोनों विश्वविद्यालयों के मध्य प्रस्तावित सहयोग को संस्थागत

समर्थन, संकाय विनिमय, छात्रवृत्ति, संस्कृत विकास योजनाओं के अंतर्गत पुस्तक सहायता तथा भारत अध्ययन एवं संस्कृत संसाधन केंद्र की स्थापना के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया गया।

कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी ने कहा कि यह समझौता केवल दो विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी नहीं बल्कि भारत और थाईलैंड के बीच ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को जोड़ने वाला सशक्त सेतु है। सिल्पकॉर्न विश्वविद्यालय में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विदेशी अध्ययन केंद्र की स्थापना दक्षिण–पूर्व एशिया में संस्कृत, पालि और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रसार का प्रमुख आधार बनेगी। साथ ही थाईलैंड के अन्य विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, संयुक्त शोध परियोजनाओं, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अकादमिक सहयोग को नई गति मिलेगी। यह ऐतिहासिक समझौता भारत और थाईलैंड के बीच शिक्षा, संस्कृति और सभ्यतागत संबंधों को सुदृढ़ करते हुए वैश्विक स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रसार का एक स्वर्णिम अध्याय सिद्ध होगा।

अगस्त में घूम आएं भारत के ये बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन, मिलेगा शानदार अनुभव

नई दिल्ली, 03 अगस्त। अगर आप भी अगस्त महीने में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपके लिए भारत की कुछ बेहतरीन जगहें लेकर आए हैं। अगस्त महीने में इन जगहों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। आइये जानते हैं आप इस महीने में किन जगहों पर जा सकते हैं?

चमोली– भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी की खूबसूरती अगस्त महीने में देखते ही बनती है। इस महीने में यह जगह कई तरह के पहाड़ी फूलों से रंग–बिरंगी हो जाती है। अगस्त का महीना यह जगह घूमने के लिए सबसे बेस्ट है।

इगतपुरी– महाराष्ट्र की सह्याद्रि पहाड़ियों में बसा इगतपुरी अगस्त के महीने में सबसे खूबसूरत दिखता है। मानसून की बारिश से भरने वाले झरने, आनंद लेने के लिए शानदार जगहें बनाते हैं। अगस्त में जब आप इस हिल स्टेशन के रास्तों पर घूमते हैं, तो कलसुबाई पीक जैसी जगहों से धुंध भरे नजारे सुकून भरा अनुभव देता है।

चेरापूंजी– अगस्त के महीने में चेरापूंजी जाने पर आपको अनोखा अनुभव मिल सकता है। घने काले बादलों और धुंध के कारण यहां का मौसम जादुई और मनमोहक हो जाता है। इस समय यहां का तापमान 20 से 25 डिग्री के बीच रहता है, और भारी बारिश की वजह से चारों तरफ हरियाल छायी रहती है।

मुन्नार– केरल के इडुक्की जिले में स्थित मुन्नार की खूबसूरती

अगस्त के मौसम में देखते ही बनती है। वेस्टर्न घाट में फैले मुन्नार के चाय के बागन अगस्त की बारिश में भीगकर एक जादुई रूप ले लेते हैं। ठंडी और धुंध के बीच, ट्रेकिंग करने वाले और प्रकृति प्रेमी इस हिल स्टेशन के हरे–भरे रास्तों और शांत सुंदरता में सुकून पाते हैं।

गोवा– अगस्त के महीने में गोवा का मानसून अपने पीक पर होता है। इस दौरान यहां चारों तरफ हरियाली और धुंध नजर आता है। दूधसागर झरना मानसून की पूरी ताकत के साथ बहता है और देखने लायक नजारा बन जाता है। इस दौरान तापमान 24 से 29 डिग्री के बीच रहता है, और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक होती है

सेनाओं को सहयोग देने वाली संस्थाओं को भी विकसित होते रहना होगा–रक्षा मंत्री

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सशस्त्र सेनाओं के साथ–साथ प्रौद्योगिकी, उद्योग, शिक्षाजगत तथा नवाचार तंत्र का जुड़ाव भी लगातार बढ़ रहा है। इसलिए जब हम इतने सारे आयामों पर आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी सशस्त्र सेनाओं को सहयोग देने वाली संस्थाओं को भी निरंतर विकसित होते रहना होगा। वह नई दिल्ली में, सशस्त्र सेना मुख्यालय (एएफएचक्यू) सिविलियन सर्विस दिवस के अवसर पर संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोला–बारूद से ही नहीं मिलती, बल्कि उन हजारों अदृश्य हाथों से भी मिलती है, जो हमेशा उसके पीछे उसके सहयोग में खड़े रहते हैं। एएफएचक्यू सिविलियन सेवाएं उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हमारी सशस्त्र सेनाएं अधिक संयुक्तता और एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में एएफएचक्यू सिविलियन सेवाओं के लिए भी यह एक बड़ा अवसर है।

उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि सैन्य और नागरिक घटकों के बीच भी संयुक्तता और एकीकरण के नए आयामों पर विचार होना चाहिए, ताकि संस्थागत स्मृति, संस्थागत स्थिरता तथा नियमों एवं विनियमों के प्रभावी अनुप्रयोग के साथ रक्षा तंत्र में और अधिक संयुक्तता लाई जा सके। एएफएचक्यू सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत स्मृति हैं। क्योंकि एएफएचक्यू संवर्ग एक ऐसी संस्था है, जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विषयगत विशेषज्ञता तथा नीतिगत स्थिरता प्रदान करता है। इसके साथ ही नागरिक–सैन्य समन्वय को सुदृढ़ करने में भी एएफएचक्यू एक महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाता है।

रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि आप अपने दायित्व और भूमिका से आगे बढ़कर रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान, भू–रणनीतिक चिंतन तथा नए विचारों के माध्यम से देश के रक्षा तंत्र को और सशक्त बनाने में योगदान दें। आप रक्षा मंत्रालय के स्थायी संवर्ग हैं और आपके पास गहन विषयगत ज्ञान है। इसलिए रक्षा से जुड़े मूल विषयों पर भी आपकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। आज हमारी स्थायी नागरिक रक्षा सेवा पुरानी सोच और पुराने तौर–तरीकों तक सीमित नहीं रह सकती। उसे भी समय के साथ विकसित होना होगा और नई क्षमताएं विकसित करनी होंगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले वर्षों में इस सेवा की पहचान भी उसकी विकसित होती भूमिका, पेशेवर उत्कृष्टता तथा विशेष योगदान को प्रतिबिंबित करे।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारा प्रयास एएफएचक्यू सिविलियन सेवाओं को धीरे–धीरे रक्षा प्रबंधन के एक पेशेवर संवर्ग के रूप में विकसित करने का होना चाहिए। ऐसा संवर्ग, जो रक्षा क्षेत्र के विभिन्न आयामों को समझता हो, संयुक्त वातावरण में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके तथा बदलती सुरक्षा और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी विशेषज्ञता को लगातार उन्नत करता रहे।–आईएएनएस

डिजिटल अंगदान पोर्टल के तहत आधार–सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का आंकड़ा 5 लाख के पार

नई दिल्ली, 03 अगस्त। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से तीन वर्षों के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का पांच लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20 हजार से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने जीवन बचाने के लिए दान किए गए अंगों को सुरक्षित रूप से परिवहन करने के महत्व पर भी बल दिया है।

सुश्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि अंग प्रत्यारोपण की संख्या के मामले में भारत अमरीका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के तहत सरकार बुनियादी ढांचे के उन्नयन, प्रत्यारोपण समन्वयकों की नियुक्ति, मृतकों के अंतिम संस्कार, अंगों का प्रबंधन और सफल प्रत्यारोपण तथा स्वास्थ्यकर्मियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के

लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अंग प्रत्यारोपण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने नागरिकों को अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने और सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।

इस अवसर पर उन्होंने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान अंगदाताओं और उनके परिवारों को सम्मानित करने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। उन्होंने ई–प्रतिरोपण का भी शुभारंभ किया, जो अंग और ऊतक दान तथा प्रत्यारोपण के लिए भारत का अगली पीढ़ी का राष्ट्रीय मंच है।

ट्राई ने लॉन्च किया नया MyCall एपः अब कॉल ड्रॉप की शिकायत करना होगा आसान

नई दिल्ली, 03 अगस्त। अगर आपकी कॉल बार–बार कटती है, आवाज टूटती है या बातचीत के दौरान दिक्कत आती है, तो अब सिर्फ शिकायत नहीं, उसका असर भी दिखेगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने MyCall एप का नया वर्जन लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स सीधे अपने कॉलिंग अनुभव की जानकारी टेलीकॉम कंपनियों तक पहुंचा सकेंगे।

इस एप का उद्देश्य यूजर्स से सीधे कॉल क्वालिटी का फीडबैक लेना और उसे संबंधित टेलीकॉम कंपनी तक पहुंचाना है, ताकि नेटवर्क से जुड़ी समस्याओं का तेजी से समाधान हो सके। TRAI के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने एप लॉन्च के दौरान कहा कि यह प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को अपनी कॉलिंग से जुड़ी परेशानियां सीधे सर्विस प्रोवाइडर्स तक पहुंचाने का आसान माध्यम देगा।

नए MyCall एप में यूजर्स किसी भी वॉयस कॉल के बाद 1 से 5 स्टार तक की रेटिंग दे सकेंगे। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी इलाके या नेटवर्क पर कॉलिंग अनुभव कैसा रहा।

सिर्फ रेटिंग ही नहीं, एप के जरिए यूजर्स कॉलिंग के

दौरान आने वाली खास समस्याओं की भी रिपोर्ट कर सकेंगे। इनमें शामिल हैं– कॉल ड्रॉप, कॉल के दौरान इको (आवाज गूंजना), ऑडियो में देरी, क्रॉस कनेक्शन, आवाज का बार–बार टूटना।

ट्राई के मुताबिक, यह फीडबैक संबंधित टेलीकॉम कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि वे नेटवर्क में सुधार के लिए जरूरी कदम उठा सकें। इस पहल का मकसद देशभर में मोबाइल कॉलिंग की गुणवत्ता बेहतर बनाना और उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है.

सूर्य का ऊपरी वायुमंडल सतह से तेज घूमता है, भारतीय वैज्ञानिकों की अहम खोज

नई दिल्ली, 03 अगस्त। भारतीय वैज्ञानिकों के एक नए अध्ययन में पता चला है कि सूर्य का ऊपरी वायुमंडल उसकी दृश्यमान सतह की तुलना में कहीं अधिक तेज गति से घूमता है। शोध में यह भी सामने आया कि सूर्य की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ उसकी घूर्णन गति भी बढ़ती है। यह खोज पारंपरिक भौतिकी की कई स्थापित धारणाओं को चुनौती देती है और अंतरिक्ष मौसम (स्पेस वेदर) की बेहतर समझ विकसित करने में मदद करेगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और अहमदनगर कॉलेज के वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन किया है। शोध के निष्कर्ष प्रतिष्ठित पत्रिका Astronomy & Astrophysics Letters में प्रकाशित हुए हैं।

वैज्ञानिकों ने जापान के नोबेयामा रेडियोहेलियोग्राफ से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि सूर्य का वायुमंडल उसकी सतह की तुलना में अधिक तेजी से घूमता है, जबकि शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार ऊंचाई बढ़ने पर घूर्णन गति कम होने की अपेक्षा की जाती है।

शोध में यह भी सामने आया कि जब सूर्य पर सनस्पॉट (सौर धब्बों) की संख्या बढ़ती है, तब ऊपरी वायुमंडल की

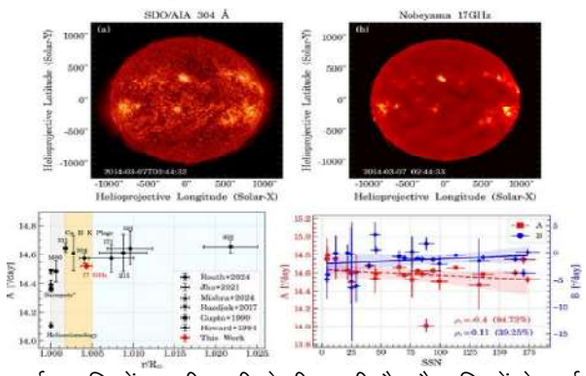

घूर्णन गति में हल्की कमी देखी जाती है। वैज्ञानिकों ने सूर्य की घूर्णन गति मापने के लिए '2D इमेज–कोरिलेशन' तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें अलग–अलग दिनों में ली गई सूर्य की तस्वीरों की तुलना कर उनके खिसकने की मात्रा के आधार पर घूर्णन वेग की गणना की गई।

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह खोज केवल सूर्य की संरचना और व्यवहार को समझने में ही नहीं, बल्कि स्पेस वेदर के अधिक सटीक पूर्वानुमान में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे भविष्य में उपग्रहों, संचार प्रणालियों, नेविगेशन नेटवर्क और बिजली अवसंरचना पर सौर गतिविधियों के प्रभाव का बेहतर आकलन किया जा सकेगा। (इनपुटःपीआईबी)